... तो हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्निकल कोर्स दिलाएगी प्रदेश में ही नौकरी के अवसर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यदि राज्य सरकार सकारात्मक रुख दिखाए तो 4 से 5 साल में प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के पास नौकरी होगी। यही नहीं युवाओं को नौकरी की तलाश में अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। यह संभव होगा केंद्र सरकार के नेशनल स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोग से संचालित सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्निकल कोर्स (सीएटी) की मदद से। यह जानकारी दी आईसीएआई के नेशनल प्रेसीडेंट राकेश सिंह ने दी। वे रविवार को आईसीएआई के लखनऊ चैप्टर की ओर से सीएमए छात्रों के लिए आयोजित 'स्मॉल अपरच्यूनिटीज आर द बिगनिंग ऑफ ग्रेट एंटरप्राइज' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

राकेश ने कहाकि बेरोजगारों को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए देश में राज्य सरकारों की मदद से आईसीएआई सीएटी की शुरुआत कर रही है। एक साल के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को अकाउंटिंग में दक्षता की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी मदद से वे सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं में सामान्य अकाउंटिंग का काम कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि केरल में राज्य सरकार की मदद से आगामी अप्रैल से इस कोर्स की शुरुआत की जा रही है। वहां की सरकार ने प्रशिक्षित बच्चों को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अकाउंटेंट के रूप में समायोजित करने की घोषणा भी की है। राजस्थान सरकार ने भी इस कोर्स के संचालन के लिए सहमति जताई गई है। फिलहाल इस विषय पर यूपी सरकार से भी संपर्क साधा गया है। यहां के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर उनके सहयोग की मांग की गई है। यदि सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाया जाता है तो आईसीएआई जल्द ही प्रदेश में भी यह कोर्स शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों के लेखा कार्यों से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के बहीखातों को तैयार करने के लिए किया जा सकेगा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने आईसीएआई के राकेश सिंह, आईसीएआई के सीसीएम संजय गुप्ता, आईसीएआई के आरसीएम सौरभ श्रीवास्तव, लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन सुनील सिंह, सेक्रेटरी विकास श्रीवास्तव एवं अन्य सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

सिर्फ बीए बीकॉम से नहीं बनेगी बात

सम्मेलन में व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में बीकॉम या एमकॉम से काम नहीं चलता। सफल होने व आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल डिग्री बहुत जरूरी है। इससे कैरिअर की राह काफी आसान हो जाती है। लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन सुनील सिंह ने बताया कि इस कोर्स को करने वाले तमाम छात्र चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफ.ओ, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंसियल कंट्रोलर, चीफ एकाउन्टेंट, चीफ इंटर्नल ऑडिटर, चीफ कास्ट कंट्रोलर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की इंडियन कास्ट एकाउन्टिंग सर्विस (आईसीएएस) ज्वॉइन करके क्लास वन ऑफीसर भी बना जा सकता है। यह सर्विस आईएएस और आईपीएस रैंक के समकक्ष होती है।

सम्मेलन में मौजूद व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र यादव, नेशनल प्रेसिडेंट राकेश सिंह व अन्य।

खरीदार न बनकर रह जाएं हम

एफडीआई के संबंध में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। राकेश सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में विदेशी कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है। अगर, इन पर नियंत्रण के बिना ही एफडीआई का रास्ता खोल दिया जाता है तो अपने मुनाफे के चक्कर में कंपनियां चीन और दूसरे देशों का सस्ता माल भारत में बेचने से नहीं चूकेंगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल पाना मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार को देश के भीतर काम कर रही कंपनियों के साथ ही किसानों और अन्य स्टेक होल्डर्स को मजबूत बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार को एफडीआई के रास्ते खोलने चाहिए लेकिन लगाम अपने हाथ में रखें।

सोच-समझ कर लागू करें एफडीआई

भारत लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में रफ्तार पकड़ने के लिए विदेशी निवेश की मदद लेना गलत नहीं है। लेकिन एफडीआई का रास्ता खोलने से पहले विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। यह कहना है आईसीएआई के नेशनल प्रेसिडेंट राकेश सिंह का। उन्होंने कहा कि एफडीआई का रास्ता खोलने से पहले सरकार को मौजूदा हालातों और इस राह से गुजर चुके दूसरे देशों के नतीजों का विश्लेषण करना चाहिए। सरकार भले ही रिटेल में एफडीआई के आने से दलालों की भूमिका खत्म करने और किसानों की स्थिति में सुधार की उम्मीद जता रही हो। लेकिन अमेरिका समेत दूसरे देशों में इसके नतीजे बहुत खराब रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसानों द्वारा आत्महत्या इसी का नतीजा है। उन्होंने सरकार को जल्दबाजी में इस दिशा में कदम न उठाने की सलाह दी।